एस.एस. निज्जर से पहले, जे

चानन कौर @ चंदन कौर और अन्य, -प्रतिवादी/अपीलकर्ता

बनाम

करतारी (मृत) अपने एल. रुपये के माध्यम से„–वादी/

आर.एस.ए. नहीं। 2015 1982 17 मार्च 2004

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - 1956 अधिनियम के तहत मृतक के प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले वादी द्वारा सिविल मुकदमा - पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले प्रतिवादी - ट्रायल कोर्ट ने वसीयत को प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित करते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलट दिया - वादी केवल वसीयत की वैधता को चुनौती दे रहे हैं - भूमि की पहचान के संबंध में कोई दलील नहीं, जो वादी द्वारा उठाए गए वसीयत का विषय-वस्तु था - ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया क्या वाद भूमि वसीयत के अंतर्गत कवर की गई थी - प्रथम अपीलीय न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत न किए गए तथ्यों के समर्थन में दिए गए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा कर रहा है - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दलीलों और प्रस्तुत तथ्यों के प्रमाण के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित कानून की अनदेखी करके खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है - प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करते हुए अपील की अनुमति दी गई।

माना गया कि वादी ने वसीयत की वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसे वैध रूप से निष्पादित नहीं किया गया था, वादी द्वारा भूमि की पहचान के संबंध में कोई याचिका नहीं उठाई गई थी, जो कि वसीयत का विषय था। ट्रायल कोर्ट द्वारा इस बारे में कोई मुद्दा तय नहीं किया गया था कि क्या वाद की भूमि वसीयत के तहत कवर की गई थी। ऐसी स्थिति होने पर, वादी द्वारा पेश किए गए किसी भी सबूत को मौखिक तर्क के समर्थन में नहीं देखा जा सकता था कि वसीयत गांव बसियाला, जिला होशियारपुर में स्थित भूमि से संबंधित नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने उन मौखिक साक्ष्यों पर भरोसा करके कानून की गलती की है जो उन तथ्यों के समर्थन में दिए गए थे जिनकी वकालत नहीं की गई थी।

वादी. ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा गलती से उलट दिया गया है।

(पैरा 14 एवं 15)

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमित जैन।

सरवन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, एन.एस. रापरी, अधिवक्ता के साथ,

उत्तरदाताओं के लिए.

निर्णय

एस.एस. निज्जर, जे..

(1) क्या किसी पक्ष द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुत नहीं की गई याचिका के समर्थन में किसी भी साक्ष्य पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, यह कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इस नियमित दूसरी अपील में उठता है।

(2) वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया है कि वे समान शेयरों के मालिक हैं और मुकदमे की भूमि में से 19 कनाल 1 मरला उनके क़ब्ज़े में हैं जो कुल भूमि 38 कनाल 3 मरला 1/2 हिस्सा है।प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सूटलैंड में कोई अधिकार या हित नहीं है और परिणामस्वरूप 12 सितंबर, 1978 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, गढ़शंकर द्वारा उत्परिवर्तन संख्या 2838 का जो निर्णय लिया गया अप्रभावी है और अपीलकर्ताओं के अधिकारों के खिलाफ है, या वैकल्पिक रूप से, मुकदमा खेवट संख्या 123/232-233 में 19 कनाल 1 मरला के संयुक्त कब्जे और 38 कनाल 3 मरला के 1/2 हिस्से के लिए है। वादी ने आरोप लगाया कि मुकदमे की जमीन का मालिक गोपी मत्ता का बेटा था, जिनकी वर्ष 1975 में मृत्यु हो गई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत वे केवल मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 से 3 मट्टा मृतक द्वारा निष्पादित कथित वसीयत के आधार पर राजस्व कर्मचारी से मिलीभगत का म्यूटेशन अपने नाम पर दर्ज करवाने में क़ामयाब रहे हैं। वादी मुकदमा भूमि पर शांतिपूर्ण कब्ज़ा होने का दावा करते हैं। प्रतिवादियों द्वारा वादी के अधिकारों को अस्वीकार करने के बाद मुकदमा दायर किया गया था।

(3) प्रतिवादियों ने वादी द्वारा ली गई दलील का खंडन किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वादी मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 का दावा है कि वे मृतक तरलोक राम की बेटियों में से एक हैं। बताया जाता है कि मृतक के तीन पुत्र हैं। कथित तौर पर 18 जून, 1975 को निष्पादित वसीयत के आधार पर वे मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। यह दावा किया जाता है कि मृतक अविवाहित था और उसकी सेवा उसकी

बेटियों और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा की जा रही थी, जिसे वह अपनी बहुओं जैसा व्यवहार किया था। वसीयत दिनांकित. 18 जून, 1975 को दर्ज किया गया था। उक्त वसीयत के आधार पर म्यूटेशन क्रमांक 2838 स्वीकृत किया गया।

4) पक्षों की दलील पर, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

1. क्या मृतक मट्टा उर्फ मस्त राम ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में 18 जून 1975 को वैध वसीयत निष्पादित की थी? ओपीडी

2. क्या आवश्यक पक्षों के नॉनजॉइंडर के लिए मुकदमा ख़राब है? ओपीडी

3. क्या याचिका में सूट भूमि का सही वर्णन नहीं किया गया है? यदि ऐसा है तो; इसका प्रभाव ? ओपीडी

4. क्या वादी को उनके कृत्यों, आचरण और स्वीकारोक्ति पर मुकदमा चलाने से रोका गया है? ओपीडी

5. क्या वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है? ओपीडी

6. क्या न्यायालय द्वारा शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का सही मूल्यांकन किया गया है? ऑप

7. राहत.

(5) ट्रायल कोर्ट, सबूतों पर चर्चा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादियों ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि वसीयत वास्तविक है और वसीयतकर्ताओं के पक्ष में स्वेच्छा से निष्पादित की गई थी। इस मुद्दे का फैसला वादी के खिलाफ और अपीलकर्ताओं के पक्ष में किया गया है। प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद संख्या 2, 3, 5 और 6 का निर्णय किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल वाद खारिज कर दिया गया है।

(6) उपरोक्त फैसले के खिलाफ, वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, होशियारपुर की अदालत में अपील दायर की। 6 सितंबर, 1982 के अपने निर्णय और डिक्री द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया है और वादी द्वारा दायर मुकदमे को प्रार्थना के अनुसार घोषणा के लिए डिक्री कर दिया गया है।

(7) निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने वर्तमान दूसरा नियमित निवेदन दायर किया है।

---

(8) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

9) ट्रायल कोर्ट के समक्ष, वादी ने यह दलील नहीं दी कि 18 जून, 1975 की वसीयत वाद भूमि से संबंधित नहीं है। यह मुकदमा वादी द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत मृतक के प्राकृतिक उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए दायर किया गया था। लिखित बयान में, प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वादी मत्ता उर्फ मस्त राम के उत्तराधिकारी नहीं हैं, जिनके तीन बेटे थे। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 एक बेटे यानी तरलोक राम की बेटियां होने का दावा करते हैं, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 तरलोक राम की विधवा होने का दावा करते हैं। लिखित बयान के पैराग्राफ 3 में, प्रतिवादियों ने यह दलील दी थी कि मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान 18 जून, 1975 को प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्रतिवादियों के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी।वादी ने 14 जून, 1979 को लिखित बयान की प्रतिकृति दायर की। लिखित बयान के पैराग्राफ 3 के जवाब में, वादी ने केवल यह कहा कि यह गलत है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

(10) ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दे के अवलोकन से, यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी ने कभी भी इस आशय का मुद्दा तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन नहीं किया कि 18 जून, 1975 की वसीयत में मुकदमे की भूमि शामिल नहीं थी। . मुद्दा केवल इस तथ्य से संबंधित है कि क्या 18 जून, 1975 की वसीयत वैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित की गई थी।

(11) पूरे मामले की जांच करने के बाद ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक की देखभाल प्रतिवादी नंबर 1 से 3 द्वारा की गई थी। यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि प्रतिवादी मटका मृतक को सेवाएं प्रदान करते थे, जो प्यार और स्नेह से 18 जून, 1975 को उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के बदले में एक वैध वसीयत निष्पादित की गई। वसीयत को विधिवत पंजीकृत किया गया था और वसीयतकर्ता ने वसीयत की सामग्री को सही माना था।

(12) ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहस के दौरान, यह प्रस्तुत किया गया था कि वसीयत, जिसे Ex.DI के रूप में निष्पादित किया गया था, उस संपत्ति को कवर नहीं करती है जो मुकदमे का विषय-वस्तु थी। यह तर्क दिया गया कि वसीयत में केवल उस संपत्ति को शामिल किया गया था जिसका उल्लेख वसीयत के ऊपरी हिस्से में किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त तर्कों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वसीयतकर्ता ने वसीयत में निम्नलिखित पंक्तियाँ शामिल की थीं: -

"मेरे बाद वही मेरे वारिस हैं। इस लाइव एनी हिवत में अपना जुमला इवहाद मनकुला वा गैर मनकुला का इंतज़ाम करना चाहता हूं तो कि बाद में कोवी इहेर्रा ना हो"।

13) इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने माना कि 'जुमला' शब्द से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता अपनी पूरी संपत्ति वसीयत के माध्यम से वसीयतकर्ताओं को देना चाहता था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वसीयतकर्ता का इरादा संपत्ति के केवल एक हिस्से की वसीयत करना होता, तो उसने "गैर मनकुला" शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होता। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वसीयतकर्ता ने अपनी पूरी संपत्ति वसीयतकर्ताओं को दे दी है। मेरी राय में, ट्रायल कोर्ट ने वसीयत की सामग्री की व्याख्या करते समय सही परीक्षण लागू किया। यह माना गया है कि न्यायालय को वसीयतकर्ता की के स्थान पर ख़ुद को रखकर वसीयत में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के संबंध में अपना दिमाग लगाना चाहिए और उसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी को उपरोक्त परीक्षण लागू करना होता, तो निष्कर्ष यह होता कि वसीयतकर्ता के दिमाग में वसीयत के लाभार्थियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि प्रतिवादी अपने मामले को "संदेह की किसी भी छाया" से परे साबित करने में सफल रहे हैं और किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है क्योंकि वसीयत खुद वसीयत करने वालों के पक्ष में बोलती है। अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को उलट दिया और माना कि वसीयत को यूपी में निष्पादित किया गया था। अपीलीय न्यायालय ने यह भी माना है कि भले ही वसीयतकर्ता ने "जुमला" शब्द का उपयोग किया है, जो अंग्रेजी शब्द "ऑल या होल" के बराबर है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि वाद संपत्ति भी वसीयत में शामिल है। अपीलीय अदालत उस बयान का भी संदर्भ देती है, जिसमें वसीयतकर्ता ने कहा था कि वह एक वसीयत बनाने का इरादा रखता है ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पूरी संपत्ति के बारे में विवाद खत्म हो सके। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, "संपूर्ण संपत्ति" शब्द और "जुमला" शब्द का उपयोग वसीयतकर्ता के उस इरादे को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिसमें वह संपत्ति शामिल है जो पंजाब में ग्राम बसियाला जिला होशियारपुर में स्थित थी। वसीयतकर्ता ने बसियाला, जिला होशियारपुर (पंजाब) क्षेत्र में स्थित संपत्ति के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयतकर्ता का उस संपत्ति को वसीयत न करने का इरादा है जो वर्तमान मामले में विवाद का विषय है। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को उलट दिया। मेरी राय में, निचली अपीलीय अदालत ने दलीलों और दलीलों के तथ्यों के सबूत के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित कानून की अनदेखी करके खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया।

(14) जैसा कि पहले देखा गया था, वादी ने वसीयत की वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसे वैध रूप से निष्पादित नहीं किया गया था। वादी द्वारा भूमि की पहचान के संबंध

में कोई याचिका नहीं उठाई गई, जो वसीयत का विषय था। ट्रायल कोर्ट द्वारा इस बारे में कोई मुद्दा तय नहीं किया गया था कि क्या वाद भूमि वसीयत के तहत कवर की गई थी । ऐसी स्थिति होने पर, वादी द्वारा पेश किए गए किसी भी साक्ष्य को मौखिक तर्क के समर्थन में नहीं देखा जा सकता था कि विल एक्ज़िबिट डीआई, गांव बसियाला, जिला होशियारपुर में स्थित भूमि से संबंधित नहीं है। सादिक महोमेद शाह बनाम माउंट सरन और अन्य (1) के मामले में, यह माना गया है कि "ऐसी दलील पर किसी भी सबूत पर गौर नहीं किया जा सकता है जिसे कभी सामने नहीं रखा गया"। प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून को भगत सिंह और अन्य बनाम जसवन्त सिंह, (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया है। हाल ही में बोन्दर सिंह और अन्य बनाम निहाल सिंह और अन्य (3) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

“जहां तक उप-किरायेदारी (शिकमी) की दलील के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से उनके विद्वान वकील द्वारा बहस की गई है, पहले हम ध्यान दें कि इस दलील को कभी भी लिखित बयान में उस तरह से नहीं लिया गया था जिस तरह से अब पेश किया गया है। लिखित बयान पूरी तरह से अस्पष्ट है और इस पहलू पर भौतिक विवरण का अभाव है। कुछ कथित राजस्व प्रविष्टियों को छोड़कर इस याचिका का समर्थन करने वाला कोई भी तत्व नहीं है। यह स्थापित कानून है कि किसी याचिका के अभाव में, उसके संबंध में दिए गए किसी भी सबूत पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उप-किरायेदारी (शिकमी) के संबंध में स्पष्ट दलील के अभाव में, प्रतिवादियों को उप-किरायेदारी (शिकमी) का मामला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि प्रतिवादी ने ऐसी कोई दलील दी होती, तो इसे मुकदमे में एक मुद्दे के रूप में जगह मिलती। हमने मुकदमे में तय किए गए मुद्दे का अध्ययन किया है। मुद्दे पर कोई मुद्दा नहीं है”।

(15) उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलीय न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करने में कानून की त्रुटि की है, जो वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए तथ्यों के समर्थन में पेश किया गया था। मेरी राय में, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा गलती से उलट दिया गया है।

(16) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है। निचली अपीलीय अदालत के 6 सितंबर, 1982 के फैसले और डिक्री को रद्द किया जाता है और ट्रायल कोर्ट के 1 सितंबर, 1980 के फैसले की पुष्टि की जाती है और वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा

आर.एन.आर.

---

(1)1930 प्रिवी काउंसिल 57
(2) एआईआर 1966 एस.सी. 1861
(3) 2003 (1) पी.एल.जे. 366